

हार्ट केयर

श्री सिद्धि विनायक

अब नियमित सेवाएं
मंदसौर में उपलब्ध

हृदय रोगों के उपचार में अंचल का जाना पहचाना नाम
हृदय रोग विशेषज्ञ
डॉ. पवन मेहता
MBBS, M.D. (Medicine) | DM (Cardiology)
Consultant Interventional Cardiology
परामर्श समर्थ -
प्रतिदिन प्रातः 10:00 से सायं 5:00 बजे तक

12, दरबार कला रोड, सिविल हॉस्पिटल के सामने, मंदसौर (म.प्र.) 07472-490333

छोटे भ्राता प्रत्युष सोमानी
को आज जन्म दिन पर

हार्दिक बधाईयां- शुभकामनाएं

--- बधाईकर्ता ---

कुणाल सोमानी एवं सोमानी परिवार, मंदसौर



साहेब गाड़ी सरकारी काम के लिए है..!

आरटीओ खुद ही नियमों को जेब में लेकर चल रहे

*** अधिकारियों की गाड़िया चल रही जनता के पेट्रोल से * सरकारी वाहनों का उपयोग हो रहा निजी काम में**

मंदसौर, 25 नवंबर गुरु एक्सप्रेस। सरकार अफसरों को वाहन सरकारी कामकाज में उपयोग करने के लिए देती है। सरकारी काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सरकारी वाहन का उपयोग किया जा सकता है। वाहन ही नहीं, पेट्रोल का रुपया भी सरकार देती है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही सरकारी गाड़ियों का खर्च उठा रही है। जिससे विभागीय काम हो सके लेकिन, जिले में कई अधिकारी ऐसे हैं जो बाजार में निजी काम के लिए इसका उपयोग करते हुए नजर आ सकते हैं। आए दिन बाजार में किसी अधिकारी की नेमप्लेट लगी सरकारी अटैच वाहन नजर आ जाएगा। स्थिति यह है कि वाहनों के रजिस्ट्रेशन, पंजीयन, लाईसेंस, जांच पड़ताल का जिम्मा उठाने वाले परिवहन विभाग के

वन विभाग का वाहन सवालियों के घेरे में ...?

वन विभाग में एक वाहन अन्त्यर्जिले का अटैच है। जबकि, अधिकांश सरकारी विभागों में स्थानीय स्तर के लोगों ने अपने वाहन अटैच कर रखे हैं। कहीं न कहीं अधिकारियों से सेंटिंग के बल पर मंदसौर से कई किमी दूर रहने वाले व्यक्ति ने अपना वाहन वन विभाग में अटैच किया है। जिसका भुगतान लगभग पचास हजार रुपए प्रतिमाह हो रहा है। यहां तक ठीक है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस वाहन के पहिए सरकारी कामों के लिए थमे हुए हैं, अधिकारी निजी काम में उपयोग कर रहा है। जबकि, उनके पास खुद का एक सरकारी वाहन उपलब्ध है?

घटना सिर्फ एक उदाहरण है।
निजी वाहनों पर नहीं लिख सकते पदनाम...

सरकारी अधिकारी अपने निजी वाहनों पर नेम प्लेट या पद नाम की प्लेट नहीं लगा सकते। सरकार ने सरकारी अधिकारियों से लेकर लोक उपक्रमों के वरीष्ठ अधिकारियों तक के लिए नियम बनाए हैं। इन नियमों के मुताबिक, सिर्फ सरकारी गाड़ियों पर ही नेम प्लेट लगाई जा सकती है। वाहनों पर नाम, पद, जाति, भूतपूर्व पद या संगठनों के पदों का नाम, गांव का नाम लिखवाना भी मना है। ऐसा करने पर एमवी एक्ट के तहत 2 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। मतलब साफ

स्मैक और केमिकल के साथ 2 तरकर धराएं, 8 आरोपी होने की खबर...?

मंदसौर, 25 नवंबर गुरु एक्सप्रेस। पुलिस कप्तान के निर्देश पर थाना पुलिस द्वारा तरकरी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दलौदा पुलिस को महती सफलता मिली है। भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुखबीर सूचना पर दलौदा थाना पुलिस ने फतेहगढ़- निरधारी फंटे से मोटर साइकिल सवार 2 युवकों को पकड़ा। इन आरोपियों के कब्जे से 275 ग्राम स्मैक और केमिकल जप्त किये जाने की जानकारी मिली है। यह भी बताया गया है कि पुलिस द्वारा पकड़े गए दोनों युवक सोनगरी से स्मैक लेकर बादाखेड़ी तरफ किसी को देने जा रहे थे। सूत्रों की माने तो पकड़ाए आरोपियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 8/29 में करीब 8 लोगो को आरोपी बनाने की तैयारी कर ली है। फिलहाल दलौदा पुलिस ने सोनगरी निवासी राजू मेवाती एवं रईस मेवाती निवासी मंदसौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है। आरोपियों से स्मैक के साथ केमिकल भी जप्त किया गया है। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा कर सकती है।

सिद्धचक्र विहार में लाखों की चोरी, नकदी और जेवरात ले गए



मंदसौर, 25 नवंबर गुरु एक्सप्रेस। शहर की सिद्ध चक्र विहार कॉलोनी में रविवार रात एक सुने मकान में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और सोने-चांदी के गहनों सहित करीब 20 लाख रुपए का सामान चुरा ले गए। मामले में कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के

नुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के सिद्ध चक्र विहार कॉलोनी के गली नम्बर 2 में स्थित मुकेश धाकड़ के मकान में बीती रात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फरियादी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। फरियादी मुकेश धाकड़ ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ शनिवार को गांव गए थे। जहां से आज सुबह एक विवाह समारोह में शामिल होने भवानी मंडी पहुंचे थे। सुबह 9 बजे पड़ोसी ने उन्हें फोन पर चोरी होने की जानकारी दी। इसके बाद दोपहर में 2 बजे वे मंदसौर पहुंचे तो घर के दरवाजे के ताले टूटे हुए थे और सारा सामान बिखरा हुआ था। मुकेश के अनुसार बदमाश सुने घर से साढ़े 6 लाख रुपए नकदी, 120 ग्राम सोना और 1 किलो वजन की चांदी की रकम चुरा ले गए। बदमाशों ने करीब 18 से 20 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया।

सीएसपी-टीआई पहुंचे मौके पर, की जांच...

रविवार को सीएसपी सतनाम सिंह, टीआई पुष्पेंद्र सिंह राठौर मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। टीआई ने बताया कि सिद्ध चक्र विहार कॉलोनी में चोरी हुई है। लेकिन, अब तक कितना सामान चोरी हुआ, इसका आकलन नहीं किया गया है।

गोदी सेठ को बचाने के लिए राजनेता व मीडिया हाऊस है, रुपए की घटती कीमत, देश की साख कौन बचाएगा..?

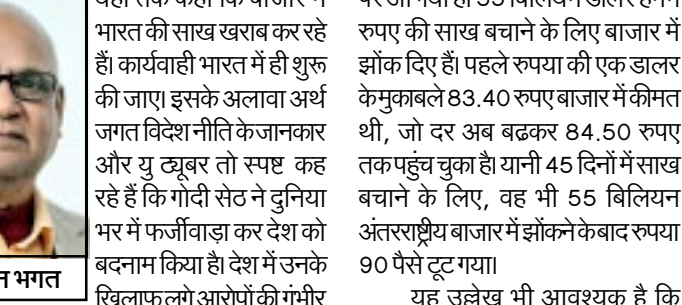
मंदसौर/उज्जैन, 25 नवंबर गुरु एक्सप्रेस। देश के राजनेताओं से लेकर उद्योगपतियों और अर्थ जगत के विद्वानों में चर्चा है कि अमेरिकी एफबीआई ने भारत के गोदी सेठ पर कार्रवाई शुरू कर दी है। विश्व समाचार अनुसार भारत के उद्योगपति गोदी सेठ के अवैध आर्थिक कारनामों को हिडेनबर्ग ने उजागर कर तहलका मचा दिया था। अब केन्या ने इसी भारतीय सेठ को दिए हुए लाखों डॉलर के कामों के अनुबंध को अपनी संसद में सबके सामने निरस्त कर दुनिया भर को यह मैसेज दे दिया कि भारतीय गोदी सेठ आर्थिक फर्जीवाड़ा करने के आदी है। इस संदेश ने दुनिया भर के उन राष्ट्रों को डराने के साथ चेता भी दिया कि अगर आप लोगों ने इस गोदी सेठ की किसी कंपनी से अनुबंध किया है तो संभल जाए। संभल गए तो बाकी राष्ट्र भी वहीं केन्या सरकार की तरह गोदी सेठ से किया हुए अनुबंध को समाप्त न कर दें।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेठ के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी, सार्वजनिक हो ही जाएगी। पर इसी के साथ जुड़ी हमारे देश की साख भी तो गिरना तय है। दुनिया भर में चर्चा है कि हमारा संविधान बहुत लचीला है। इसीलिए कार्रवाई की गति धीमी होती है। और दोषसिद्ध होने में भी समय लगता है। किन्तु, विदेशी कानून किसी भी आपराधिक कार्रवाई पर कानून के संरक्षक से पहले आधिकारिक सबूत को एकत्रित कर आधार बनाया जाता है। जिसे पुख्ता कार्रवाई कह सकते हैं। एसबीआई के इस प्रकरण ने भारत के अनेक वर्ग को दो हिस्सों में बांट दिया है। जैसे वर्तमान सरकार के समर्थक मीडिया हॉउस गोदी सेठ पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए का विषय इसलिये भी है कि हमसे छोटे देश की करेसी भारत के मुकाबले बेहतर

स्थिति में है। डेढ़ माह पहले भारत के पास 705 बिलियन विदेशी एक्सचेंज का रिजर्व था, यही अब गिरकर 650 बिलियन डॉलर पर आ गया है। 55 बिलियन डॉलर हमने रुपए की साख बचाने के लिए बाजार में झोंक दिए हैं। पहले रुपया की एक डालर के मुकाबले 83.40 रुपए बाजार में कीमत थी, जो दर अब बढ़कर 84.50 रुपए तक पहुंच चुका है। यानी 45 दिनों में साख बचाने के लिए, वह भी 55 बिलियन अंतरराष्ट्रीय बाजार में झोंकने के बाद रुपया 90 पैसे टूट गया।

यह उल्लेख भी आवश्यक है कि विदेशी एक्सचेंज की राशि को एक सीमा तक ही रुपयों को बचाने के लिए खर्च कर सकते हैं। उसके बाद रुपए की साख को कैसे बचाएं। भारत में सरकार किसी की बने बहुमत से बने या अत्यधिक बहुमत से बने, कांग्रेस की बने या बीजेपी की। इससे इसलिये भी है कि हमसे छोटे देश की करेसी भारत के मुकाबले बेहतर

हैं। व्यापार की स्थिति भी देखिए, हमने आयात सिर्फ चीन से ही पिछले अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने में 57 बिलियन डॉलर का किया था। जबकि निर्यात सिर्फ 6 बिलियन डॉलर का किया। अंदाज लगाइए चीन को ही हम 9 गुना ज्यादा डॉलर का मुनाफा आयात के बदले में कर रहे। और सिर्फ एक गुना निर्यात के बदले पाएंगे तो रुपए साल भर में ही डॉलर के मुकाबले कितना गिर जाएगा। जबकि, इन्हीं 6 महीने में भारत का कुल निर्यात 393.22 बिलियन तथा आयात 448.05 बिलियन डॉलर का होना दर्शाया गया है। सरकार आ रही है, जा रही है। शेखी भी बघारा रही है। इधर गोदी सेठ के लिए भी धिंधा पालने वाले अनेक हैं। पर भारत के रुपए की गिरती साख पर ध्यान नहीं दिया तो देश के साथ देशवासियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय पर नकारात्मक असर पड़ना निश्चित तय हो जाएगा।



चन्द्रमोहन भगत

जांच कराना चाहिए। देश की जनता को गोदी सेठ का सच जानने का अधिकार है। देश की साख के साथ रुपए की अंतरराष्ट्रीय कीमत भी लगातार गिरती जा रही है। इससे भी भारत की वैश्विक साख पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। चिंता का विषय इसलिये भी है कि हमसे छोटे देश की करेसी भारत के मुकाबले बेहतर

हैं। व्यापार की स्थिति भी देखिए, हमने आयात सिर्फ चीन से ही पिछले अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने में 57 बिलियन डॉलर का किया था। जबकि निर्यात सिर्फ 6 बिलियन डॉलर का किया। अंदाज लगाइए चीन को ही हम 9 गुना ज्यादा डॉलर का मुनाफा आयात के बदले में कर रहे। और सिर्फ एक गुना निर्यात के बदले पाएंगे तो रुपए साल भर में ही डॉलर के मुकाबले कितना गिर जाएगा। जबकि, इन्हीं 6 महीने में भारत का कुल निर्यात 393.22 बिलियन तथा आयात 448.05 बिलियन डॉलर का होना दर्शाया गया है। सरकार आ रही है, जा रही है। शेखी भी बघारा रही है। इधर गोदी सेठ के लिए भी धिंधा पालने वाले अनेक हैं। पर भारत के रुपए की गिरती साख पर ध्यान नहीं दिया तो देश के साथ देशवासियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय पर नकारात्मक असर पड़ना निश्चित तय हो जाएगा।

हैं। व्यापार की स्थिति भी देखिए, हमने आयात सिर्फ चीन से ही पिछले अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने में 57 बिलियन डॉलर का किया था। जबकि निर्यात सिर्फ 6 बिलियन डॉलर का किया। अंदाज लगाइए चीन को ही हम 9 गुना ज्यादा डॉलर का मुनाफा आयात के बदले में कर रहे। और सिर्फ एक गुना निर्यात के बदले पाएंगे तो रुपए साल भर में ही डॉलर के मुकाबले कितना गिर जाएगा। जबकि, इन्हीं 6 महीने में भारत का कुल निर्यात 393.22 बिलियन तथा आयात 448.05 बिलियन डॉलर का होना दर्शाया गया है। सरकार आ रही है, जा रही है। शेखी भी बघारा रही है। इधर गोदी सेठ के लिए भी धिंधा पालने वाले अनेक हैं। पर भारत के रुपए की गिरती साख पर ध्यान नहीं दिया तो देश के साथ देशवासियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय पर नकारात्मक असर पड़ना निश्चित तय हो जाएगा।

हैं। व्यापार की स्थिति भी देखिए, हमने आयात सिर्फ चीन से ही पिछले अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने में 57 बिलियन डॉलर का किया था। जबकि निर्यात सिर्फ 6 बिलियन डॉलर का किया। अंदाज लगाइए चीन को ही हम 9 गुना ज्यादा डॉलर का मुनाफा आयात के बदले में कर रहे। और सिर्फ एक गुना निर्यात के बदले पाएंगे तो रुपए साल भर में ही डॉलर के मुकाबले कितना गिर जाएगा। जबकि, इन्हीं 6 महीने में भारत का कुल निर्यात 393.22 बिलियन तथा आयात 448.05 बिलियन डॉलर का होना दर्शाया गया है। सरकार आ रही है, जा रही है। शेखी भी बघारा रही है। इधर गोदी सेठ के लिए भी धिंधा पालने वाले अनेक हैं। पर भारत के रुपए की गिरती साख पर ध्यान नहीं दिया तो देश के साथ देशवासियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय पर नकारात्मक असर पड़ना निश्चित तय हो जाएगा।

बुलंदियो के आसमान को छुना तुम चांद बनकर ।

जीवन में महको तुम गुलशन की शान बनकर ।।

हमारे परम प्रिय, मां सरस्वती के वरद पुत्र, दैनिक गुरु एक्सप्रेस के संपादक

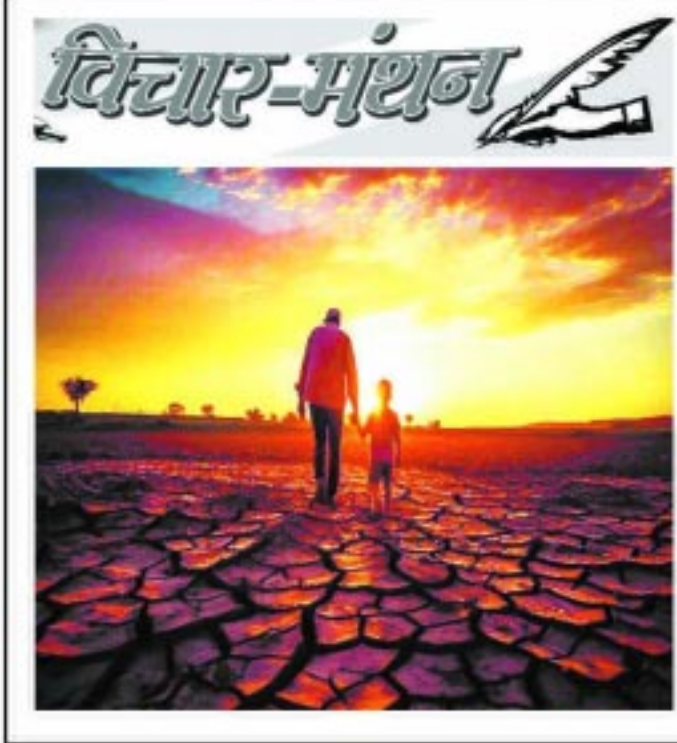
श्री आशुतोष नवाल

को आज जन्मदिवस पर

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

***** बधाईकर्ता *****

विनोद सम्राट, आलोक शर्मा, विनोद डगवर, कन्हैयालाल दया, मनजीतसिंह टूटेजा मनी, भूपेन्द्र सांखला, पंकज जैन (तिलक), उत्कर्ष मण्डोवरा (पिण्डू), आशीष जैन (सौरभ बूध), हेमन्त बुलचंदानी, जितेश पण्ड्या, राजू राठौर, घनश्याम शर्मा कानू, पप्पू सरोगा खानपुरा, सुनील ठाकुर कंदील, दीपक साहू (गज्जू सम्राट), विक्रम सम्राट, संदीप साहू (चीता), हेमन्त आडवाणी, सुरेश होतवानी (सूरी), आशीष नवाल, भारतसिंह तोमर, सचिन जैन, पिण्डू शर्मा, हरिश मण्डोवरा, जीआर सोनगरा, संजीव परमार, संदीप बारोदिया, प्रीतमसिंह सौलकी, श्याम ग्वाला बम, लखन ग्वाला, कुणाल सोमानी, ओमप्रकाश बारोदिया, रोहित शुक्ला, प्रांजल शर्मा एवं मित्र मण्डल, मंदसौर (म.प्र.)



जलवायु संकट की जिम्मेदारी केवल विकासशील देशों पर है?

दुनिया भर में जलवायु पर मंडराते संकट का दायरा इतना व्यापक और गंभीर है कि विश्व के सभी देश चिंतित हैं और मिल-बैठ कर इसका समाधान निकालना चाहते हैं। इस मकसद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु सम्मेलन होते रहते हैं। मगर इससे बढ़ी विडंबना और क्या होगी कि दशकों से हर वर्ष आयोजित सम्मेलन में ज्यादातर देशों की हिस्सेदारी के बावजूद अब तक कोई ऐसा खाका सामने नहीं आ सका है, जिसमें जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों के मसले पर एक न्यायपूर्ण दृष्टि अपनाई जाए और उस पर सभी देशों की सहमति बने। नतीजतन, जलवायु संकट पर आयोजित सम्मेलनों के बाद अब तक कोई ठोस प्रारूप सामने नहीं आ

सका है। इस मसले की गंभीरता को समझने और स्वीकार करने के बावजूद ज्यादातर देशों के बीच मतभेद और अपनी जवाबदेही से दूर भागने की प्रवृत्ति क्यों बनी हुई है? गौरतलब है कि इस वर्ष अजर्नैजान के बाकू में हुए सीओपी-29 में भी विकसित और विकासशील देशों के बीच समस्याओं की गहराई पर विचार में कोई कमी नहीं देखी गई, मगर समाधान के रास्ते और जिम्मेदारियों के स्तर पर सहमति नहीं बनी। बाकू में विकासशील देशों के लिए नए जलवायु वित्त पैकेज का मसविदा तो पेश किया गया, लेकिन उसमें प्रमुख मुद्दे बरकरार रहे। दरअसल, विकसित देश अब भी इस सवाल का जवाब देने से कतरा रहे हैं कि वे 2025 से

विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हर वर्ष कितना वित्तीय सहयोग देने को तैयार हैं। विकासशील देशों ने लगातार इस पक्ष को उठाया है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटीती और जलवायु अनुकूलन के लिए उन्हें कम से कम तेरह खरब अमेरिकी डॉलर की जरूरत है। विचित्र यह है कि बाकू में पेश संशोधित मसविदे में विकसित देशों से वित्तीय सहयोग की जरूरत के पहलु को तो स्वीकार किया गया, लेकिन इस पर सहमति के मामले में कोई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं हुई। यह समझना मुश्किल नहीं है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटीती के उपाय लागू करने के संदर्भ में विकासशील देशों को किन जटिल

स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है! इसमें कोई दोरारा नहीं कि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन जलवायु संकट के लिए सबसे बड़े कारकों में से एक है और बिना देरी किए इसका समाधान निकालने के लिए रास्ते तलाशने की जरूरत है। मगर सवाल है कि क्या इसके लिए केवल विकासशील देश जिम्मेदार हैं। जब भी इस समस्या के दूसरे और इसकी जिम्मेदारी लेने की बात उठती जाती है तो विकसित देशों की ओर से आखिर किन वजहों से कार्बन उत्सर्जन को मुख्य सवाल बनाने की कोशिश होती है? इन्हीं वजहों से गुरुवार को भारत को यह स्पष्ट रूप से कहना पड़ा कि यह विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त से ध्यान हटा कर उत्सर्जन

में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित करने के विकसित देशों के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं करेगा। यह छिपा नहीं है कि विकासशील देशों में अभी विकास किस स्तर की चुनौतियों से गुजर रहा है, जबकि विकसित देशों में संसाधनों और सुविधाओं के उपभोग की स्थिति यह है कि जलवायु संकट के लिए जिम्मेदार ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को लेकर अक्सर वही कठपंरे में खड़े पाए जाते हैं। विकसित देशों में जलवायु से जुड़े खतरों को लेकर चिंता है, तो जरूरत इस बात की है कि इस समस्या की जिम्मेदारी विकासशील देशों पर थोपने के बजाय वे खुद आगे आकर इसके ठोस हल का रास्ता निकालने में अपनी भूमिका तय करें।

आरोप भारत में लगाया तो अमेरिका में जांच कैसे शुरू हो गई?

कमलेश पांडे
बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस ने अदानी पर भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर (2200 करोड़ रुपए से ज्यादा) की रिश्त देने का आरोप लगाया है, जो एक गम्भीर बात है। क्योंकि यूएस अटॉर्नी ऑफिस ने आरोप में कहा है कि अदानी ने अपनी कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी को सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्त दी है। मसलन, अदानी पर आरोप है कि उन्होंने 2021 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उसके बाद राज्य सरकार 7,000 मेगावाट बिजली खरीदने पर सहमत हुई थी। आंध्र के अधिकारियों को 25 लाख रुपये प्रति मेगावाट की दर से कथित रिश्त दी गई। इसके अलावा, अमेरिकी सिविलरिजिटर एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया। खास बात यह है कि उन्होंने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और इन्वेस्टर्स से छिपाया है, जिससे अदानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। लिहाजा, अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स का दावा है कि कंपनी के दूसरे सीनियर अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को पैसा देने पर सहमति जताई थी। बता दें कि अदानी समूह ने

साल 2021 में एक बॉन्ड ऑफर कर अमेरिका के अलावा दूसरे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और अमेरिका के बैंकों से फंड जुटाया है। अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी) ने बयान में कहा है कि कथित साक्षिज्ञ के तहत अदानी ग्रीन ने अमेरिकी निवेशकों से 17.5 करोड़ डॉलर से अधिक जुटाए और एंज्यूर पावर का शेयर न्यूयॉर्क शेयर बाजार में लिस्टेड किया। साथ ही, न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने अदानी, सागर अदानी, सिरिल कैबनेस और अदानी ग्रीन और एंज्यूर पावर से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए हैं। वहीं, अदानी ग्रुप ने रिश्तखोरी के आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें बेवुनियाद बताया है। उसने कहा है कि ग्रुप सभी कानूनों का पालन करता रहा है। यह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। ग्रुप के प्रवक्ता ने अमेरिकी न्याय विभाग के बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया जिसका अदानी पर यह केवल आरोप है और जब तक दोष साबित न हो जाए तब तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाएगा। लिहाजा, बयान में कहा गया कि हम आश्चर्य करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाले संगठन हैं। अदानी ग्रुप ने अदानी ग्रीन एनर्जी लि. के 60 करोड़ डॉलर के बॉण्ड को रद्द कर दिया है। उल्लेखनीय है कि अदानी ग्रीन एनर्जी को गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश



सहित कई राज्यों में ठेका मिला है। ऐसे में यह स्वाभाविक सवाल है कि जब भारत में रिश्त देने के आरोप लगाए गए हैं तो फिर केस यूएस यानी अमेरिका में क्यों? इसका जवाब यही है कि अमेरिकी कानून अपने निवेशकों या बाजारों से जुड़े विदेशों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। चूंकि, प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्त के रूप में देना अपराध है, इसलिए अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ। चूंकि अमेरिका भारत का मित्र देश भी है, इसलिए ये आरोप अहम हैं। हालांकि, जिस तरह से अमेरिकी चुनावों में परास्त राष्ट्रपति जो बाइडेन के मातहत प्रशासन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को भड़काने और भारत के उद्योगपति को भ्रष्टाचार के मामले में उलझाने की पहल दिला-जाते की है, इसके अंतर्राष्ट्रीय सियासी मायने को भी समझने की जरूरत है। शायद वह भावी ट्रंक

प्रशासन के लिए मुश्किलें पैदा करना चाहता हो। सवाल यह है कि आखिर यह झगडा किन-किन प्रोजेक्ट्स को लेकर मचा है? तो जवाब यही होगा कि अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार, एनर्जी कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष नौम अदानी हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अदानी है, जो उनके भतीजे हैं। इसके अलावा, एंज्यूर पावर के सीईओ रहे रंजीत गुप्ता, एंज्यूर पावर में सलाहकार रुपेश अग्रवाल अमेरिकी इश्यूअर हैं। हुआ यह है कि अदानी ग्रीन एनर्जी और अमेरिकी इश्यूअर ने सरकारी स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी उपलब्ध कराने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। हालांकि, एसईसीआई को सौर ऊर्जा खरीदने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल पाए। लिहाजा खरीदारों के बिना सौदा आगे नहीं बढ़ सकता था और दोनों कंपनियों के सामने बड़े नुकसान का जोखिम था। इसलिए अदानी ग्रुप और एंज्यूर पावर ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्त देने की योजना बनाई। तो फिर यह सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर में रिश्त का हिस्सा किनको किनको मिला? उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा किनको मिला? इसके जवाब भी अमेरिकी प्रशासन के आरोपों से मिलते हैं। अमेरिकी प्रशासन के आरोपों के मुताबिक, इन लोगों ने तय किया कि सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी

कि वो राज्य बिजली वितरण कंपनियों को एसईसीआई के साथ बिजली आपूर्ति समझौते में शामिल होने के लिए तैयार करेंगे। शायद इसलिए उन्होंने भारतीय अफसरों को करीब 265 मिलियन डॉलर की रिश्त देने का वादा किया, जिसका एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को दिया गया। फलाफल यह निकला कि इसके बाद कुछ राज्य बिजली कंपनियों सहमत हुईं और दोनों कंपनियों से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए एसईसीआई के साथ समझौता किया। इससे साफ है कि भारतीय ऊर्जा कंपनी और अमेरिकी इश्यूअर ने मिलकर रिश्त का भुगतान किया। इतना ही नहीं, अपनी सलिसता छिपाने के लिए कोड नामों का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय (न्यू यॉर्क) के अनुसार, रिश्तखोरी और धोखाधड़ी के मामले में जिन्हें आरोपी बनाया गया है उनमें नौम अदानी, सागर एस. अदानी, विनीत एस. जैन, रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्लोत्रा, रुपेश अग्रवाल के नाम प्रमुख हैं। हालांकि, अमेरिकी कानूनों के तहत ऐसे मामलों में आमतौर पर डेफेंड प्रॉसिक्यूशन एग्जीमेट्स या नॉन प्रॉसिक्यूशन एग्जीमेट्स के जरिए सेटलमेंट की इजाजत है। जिसके मुताल्लिक कुछ गलतियां स्वीकार करने, नियमों का अनुपालन बेहतर करने के वादे और जुर्माना चुकाने के साथ ही यह मामला सुलझाया जा सकता है।

वेदों और उपनिषदों की गहराइयों में छिपे रहस्य...

राजेंद्र जोशी
दरअसल, भारतीय ज्ञान परंपरा दुनिया भर में समृद्ध और सबसे प्राचीन परंपराओं में से मानी जाती है। मगर आज यह कोई मुख्य विषय नहीं है। सवाल है कि फिर भारतीय ज्ञान परंपरा से परहेज किसको है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय ज्ञान और संस्कृति को कमजोर करने का जो बारीक प्रयास हुआ, उसे आजादी के बाद वापस समृद्ध करने की कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। हालांकि इसका गुणगान करने में कोई कमी नहीं की जाती है। सवाल है कि हमारे देश के विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखती है। देश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग नहीं है। उपनिषदों, पुराणों और वेदों जैसे विषयों में इसका विस्तार हमें पढ़ने को मिलता है। हमारे वेद उपनिषद में योग और ध्यान, आयुर्वेद चिकित्सा, दर्शन और न्याय जैसे विषय भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख विषय रहे हैं। यह किसी व्यक्तिगत समूह या व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बल्कि यह प्राचीन परंपराओं का दर्शन रहा। वहीं हमारे देश में शिक्षा को उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति था और आज की शिक्षा उपार्धि-पत्र प्राप्ति तक सिमट कर रह गई है। भारत सदियों से ज्ञान परंपरा और संस्कृति के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। परंपरागत ज्ञान भाषा, दर्शन, ज्ञान की अपरिहार्यता, लोक, मूर्तिकला पर आधारित है। कहने को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्राचीन ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा का समावेश करते हुए शिक्षा प्रणाली को आगे ले जाने की बात की जा रही है, लेकिन अब तक देश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय को सुचिंतित तरीके से शुरू करने को लेकर पहल नहीं हुई है। हालांकि जिन कुछ विश्वविद्यालयों में यह विषय पहले से संचालित है, उनका उदाहरण हमारे सामने है। विगत तीन सौ वर्षों में इसका लोप हुआ है। भारतीय ज्ञान परंपरा वैदिक और उपनिषद काल के बाद बौद्ध और जैन काल में भी कायम रही। ऋग्वेद में लिखा है- 'आ नो भद्राः क्रतवो यंतु विश्वतः' यानी सात्विक विचार हर दिशा से आने चाहिए। स्वयं को भी अन्य को किसी चीज से वंचित नहीं करना चाहिए। ज्ञान की बातों को ग्रहण करना चाहिए। वेद और वेदवांगमय भारतीय ज्ञान परंपरा की आत्मा है। भारतीय जीवन-दर्शन को जो स्वरूप



वेद-उपनिषदों से ही मिला है, वह भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल में है। भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल में वेद विचार को भी महत्वपूर्ण बनाता है। वर्तमान युग में वेद अध्ययन और वैदिक परंपरा का उल्लेख प्रत्येक ग्रंथ में देखने और सुनने को मिलता है। भारतीय विश्वविद्यालयों में वेदों और वैदिक वांगमय पर हुए अनुसंधान कार्यों से भारतीय ज्ञान परंपरा की जो उपदेयता बनी है, वह आने वाली पीढ़ी के समग्र रहस्य जानने चाहिए। वैदिक परंपरा का संरक्षण एवं संवर्धन भारतीय ज्ञान परंपरा करती है। आधुनिक ज्ञान के खेत भी वेद ही है। वैदिक विचारों की सामाजिक उपयोगिता, वैदिक चिंतन और विश्व शांति जैसे सवाल का जवाब भारतीय ज्ञान परंपरा के पठन-पाठन से ही संभव है। भविष्य में जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर कैसे बनाया जाए, यह हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में छिपा हुआ है। नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान से परिचित करने के लिए ठोस पहल होनी चाहिए, ताकि हमारे अतीत में क्या अच्छा रहा है या क्या अच्छा नहीं रहा, इस पर विवेक आधारित विश्लेषणात्मक चिंतन परंपरा मजबूत हो। वेद और उपनिषदों के अध्ययन से आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान ने भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनात्मकता को प्रभावित किया है, वहीं अनेक गूढ़ रहस्यों का विवरण भी देखने को मिलता है। योग और ध्यान रोजगार के बड़े साधन के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। भारतीय दर्शन और न्याय जीवन कर्म, धर्म, मोक्ष और सत्य को उच्चतम विचारों की व्याख्या ही है, जो वर्तमान समाज की प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय ज्ञान परंपरा को विद्यार्थियों के बीच पहुंचाए जाने से हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए करियर के अवसर भी पैदा होंगे और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को भी बल मिलेगा। विचारणीय सवाल यह है कि पिछले एक दशक में भारतीय ज्ञान परंपरा को महान बताने के बावजूद ठोस रूप से इसके अध्ययन-मनन की बात कौन कर रहा है।

स्टेडियम कमेटी को दुकानों से प्राप्त राशि खिलाड़ियों एवं खेल मैदान पर खर्च करना चाहिए-अग्रवाल

नोबल क्रिकेट अकादमी द्वारा आयोजित टी-20 क्रिकेट स्पर्धा में डायनेमिक इलेवन विजेता रही

मंदसौर, 25 नवंबर गुरु एक्सप्रेस। क्रिकेट खेल अनिश्चितता का खेल है कब कौन अचानक विजेता बन जाता है यह कह नहीं सकते हैं। हर गेंद पर अलग-अलग स्थिति निर्मित हो जाती है। मैदान को जिंदा खिलाड़ियों ने रख रखा है मंदसौर में क्रिकेट के प्रति जो अपार उत्साह देखने को मिलता है वह वास्तव में नोबेल क्रिकेट अकादमी जैसी संस्थाओं की वजह से ही देखने को मिल पाता है। स्टेडियम कमेटी को जो दुकानों से किराया प्राप्त होता है वह किराया राशि मैदान के रखरखाव और खिलाड़ियों के उम्र खर्च करना चाहिए।

श्री बंशीलाल टॉक, श्री सईद भाई खेडे वाले, सलीम भाई प्रेस वाले आदि मंचस्थ थे। नेशनल मीडिया फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने कहा कि मंदसौर का स्टेडियम मैदान काफी अच्छा है इस मैदान के आसपास बड़ी संख्या में दुकानों का निर्माण है और उनसे किराया की आमदनी भी प्राप्त होती है किराए से प्राप्त आमदनी मैदान के रखरखाव एवं खिलाड़ियों पर यदि खर्च होगी तो निश्चित रूप से मंदसौर के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। नोबल क्रिकेट अकादमी द्वारा आयोजित क्रिकेट स्पर्धा में 8 टीमें ने भाग लिया जिसमें नोबल क्रिकेट अकादमी, दशपुर क्रिकेट अकादमी, एस पी इलेवन, दशपुर क्लब इलेवन, डायनेमिक इलेवन, सुल्तान इलेवन, डी के इलेवन ने सम्मिलित थीं। जिसमें एसपी इलेवन और डायनामिक इलेवन के मध्य फाइनल मैच हुआ जिसमें एसपी इलेवन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया एसपी इलेवन के खिलाड़ियों ने 20 ओवर में 151 रन 6 विकेट के नुकसान पर



बनाए। जिसमें भारत वाइज 13 रन, शमी पोरवाल 41 रन, भूक भैया 28 रन और दिलीप सिंह ने 34 रन का योगदान दिया। डायनेमिक इलेवन की ओर से राशिद खान ने तीन विकेट लिए, कमल सिंह ने दो विकेट लिए इसके जवाब में डायनेमिक इलेवन में 20 ओवर में 155 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाकर 6 विकेट से जीत हासिल की। डायनेमिक इलेवन की ओर से विशाल हिरानी ने 66 रन, हिमांशु चौहान ने 35 रन, बंटी ने 30 रन और कमल सिंह ने 12 रन का योगदान दिया। फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच विशाल हिरानी रहे। विजेता टीम

को 11000 नगद व ट्रॉफी और उपविजेता टीम को 5000 व ट्रॉफी अतिथि द्वारा प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालक नोबल क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष साबिर भाई पान वाले ने किया तथा आभार समीर खान ने माना।

जिला स्तरीय जनसुनवाई मल्हारगढ़ में आज

मंदसौर, 25 नवंबर गुरु एक्सप्रेस। अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल द्वारा बताया गया कि 26 नवंबर, मंगलवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई मल्हारगढ़ जनपद पंचायत सभागार में प्रातः 11 बजे से आयोजित होगी। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग आम जनों की समस्याओं को सुनेगी तथा निराकरण करेंगी।

अवैध शराब सहित पकड़ा

पिपलियामंडी, 25 नवंबर गुरु एक्सप्रेस। पुलिस ने अवैध शराब सहित आरोपियों को पकड़ा। पिपलिया पुलिस ने 5 लीटर हाथ भंडी कच्ची शराब सहित अन्वाव निवास बबलू पिता बंशीलाल को, मल्हारगढ़ पुलिस ने 16 क्वार्टर के साथ लसुडिया कदमाला निवासी राजू पिता गोवर्धनलाल को पकड़ा। इसी तरह मल्हारगढ़ पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए छोट्टी गुडमाली निवासी शंभूलाल पिता नंदराम को पकड़ा।

सोयाबीन खरीदी हेतु पुर्णायु वेयर हाउस घसोई में बनाया

मंदसौर, 25 नवंबर गुरु एक्सप्रेस। कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग ने बताया कि सोयाबीन खरीदी हेतु पुर्णायु वेयर हाउस घसोई में खरीदी केन्द्र बनाया गया है। इस केन्द्र पर पंजीकृत किसानों के 31 दिसम्बर 2024 तक खरीदी होगी। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित रुनिजा केपुंजीकृत किसान से ही खरीदी की जावेगी।



पानी की चोरी के मामलों पर सख्त कार्यवाही करें-कलेक्टर

हम होंगे कामयाब पखवाड़ा 10 दिसंबर तक चलेगा, सामाहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न

मंदसौर, 25 नवंबर गुरु एक्सप्रेस। कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग की अध्यक्षता में सामाहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक सुशासन भवन स्थित सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी एसडीएम, नगर पालिका, सीएमओ को निर्देश देते हुए कहा कि, पानी की चोरी के मामलों एवं शिकायत पर सख्त कार्यवाही करें। वहीं भी पानी की चोरी को लेकर कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। बैठक के दौरान सीईओ, जिला पंचायत श्री राजेश कुमार जैन,

अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, सभी जिलाधिकारी मौजूद थे। हम होंगे कामयाब पखवाड़ा 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इस पखवाड़े में जेडए आधारित हिंसा उन्मूलन हेतु जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम होंगे। इसमें सभी विभाग अपनी-अपनी गतिविधियां आयोजित करें। जल संसाधन विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि, सिंचाई परियोजना द्वारा किसानों के खेतों में पानी भर जाने से अगर किसी किसान की फसल को नुकसान हुआ है तो किसान को मुआवजा देने की कार्यवाही करें। कृषि विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि खाद की पर्याप्त उपलब्धता रहे। खाद को लेकर किसी प्रकार की समस्या ना हो। स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए डोर डूअर कैपेन लगाता चलाए। इसके लिए नगरीय निकाय के सीएमओ और उनके स्टफ को प्रशिक्षण प्रदान करें। भूमि आवंटन के प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करें। जिससे भूमि आवंटन में आगे की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

